बुलडोजर अब यूपी का ब्रांड, यहां बनेगा तो देश विदेश में मांग खुद बढ़ेगी- मुख्यमंत्री

सीएनएच ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह अब कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने यूपी को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब यूपी का ब्रांड बन चुका है। अगर कंपनियां यहां बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाएंगी, तो देश विदेश में इसकी मांग स्वत: ही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सीएनएच इंडस्ट्रियल के नए ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में ?1200 करोड़ से अधिक की लागत से यह प्लांट स्थापित हो रहा है।मुख्यमंत्री ने जेवर क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में कभी गोलियां चलती थीं और जो अपराध दर में सबसे ज्यादा बदनाम था, वह जेवर आज भारत के 'गहने' के रूप में निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और यीडा के विकास के साथ यह पूरा क्षेत्र एक बड़े औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहां एचसीएल फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और डाटा सेंटर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं आकार ले रही हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामने पलायन, पिछड़ेपन और अराजकता जैसे कई प्रश्न थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फियरलेस बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि राज्य टॉप अचीवर रहा है और डीरेग्युलेशन में देश में प्रथम स्थान पर है। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला यूपी आज बॉटम फाइव से बाहर निकलकर देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में एक बार फिर बरेली अव्वल

लखनऊ, योगी सरकार द्वारा पिछले साढ़े नौ वर्षों से प्रदेश में सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर साफ देखा जा सकता है। सीएम डैशबोर्ड की अक्टूबर माह की समग्र रैंकिंग में एक बार फिर बरेली ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं पीलीभीत ने दूसरा और रामपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बरेली, पीलीभीत और रामपुर के जिलाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह उपलब्धि जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण, बेहतर फीडबैक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधारात्मक पहल से हासिल किया है। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट उन जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और राजस्व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप बरेली में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

11 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट- मुख्यमंत्री

24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मनेगी देव दीपावली

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में गंगा महोत्सव और देव दीपावली की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देव दीपावली काशी की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली पर्व है। देश-दुनिया से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों और सामने आई समस्याओं को ध्यान में रखकर इस बार बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी को परेशानी न हो। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और तय समय-सीमा में सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए।समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष गंगा महोत्सव 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर आयोजित होगा। चारों दिन सांस्कृतिक संध्या होगी। मुख्यमंत्री ने इसमें स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इस बार सभी पक्के घाटों, गंगा के सामने वाले रेतीले तट और शहर के 100 से अधिक कुंडों पर 11 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें महिला स्वावलंबन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार दीपक भी शामिल किए गए हैं। दीप प्रज्वलन की व्यवस्था के लिए पूरे घाट क्षेत्र और रेतीले तट को सेक्टरों में बांटकर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देव दीपावली का उल्लास केवल घाटों तक सीमित न रहे, बल्कि समूची काशी में इसका प्रभाव दिखाई दे। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ सारनाथ, मार्कण्डेय महादेव मंदिर, शूलटंकेश्वर मंदिर और प्रमुख कुंडों पर भी दीपोत्सव के विशेष प्रबंध किए जाएं। 24 नवंबर को ही गुरु नानक जयंती होने के कारण गुरुद्वारों में लंगर, कीर्तन और संगत की व्यवस्थाएं भी समय से पूरी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नाविकों से संवाद कर उनका सुरक्षा और सुव्यवस्था की दृष्टि से प्रशिक्षण कराने की जरूरत पर बल दिया।अधिकारियों ने मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 24 नवंबर की शाम सभी घाटों पर दीप प्रज्वलित होंगे और दशाश्वमेध घाट पर विश्वप्रसिद्ध महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद चेत सिंह घाट पर भव्य प्रोजेक्शन एवं लेजर शो, दशाश्वमेध व अस्सी घाट के सामने ड्रोन शो तथा काशी विश्वनाथ धाम घाट के सामने ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए।

सीएम योगी ने शिवराज सिंह चौहान की मां को दी श्रद्धांजलि

भोपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने यहां केंद्रीय कृषि मंत्री व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि दी। शिवराज सिंह चौहान की मां काशी बाई का गत 30 अक्टूबर को निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिवंगत माताजी के त्रयोदशी संस्कार एवं शांति भोज में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने स्मृतिशेष काशी बाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिवार को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह आदि ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।



सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा ज्ञापन

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को ज्ञापन देकर मांग की है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधान सभा की मतदाता सूची से 1 करोड 27 लाख हिन्दू मतदाताओं के नाम गायब होने के कथन को संज्ञान में लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा श्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी करके उनसे शपथ-पत्र मांग लिया जाये। देश एवं कई प्रदेशों के विपक्षी नेताओं द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाये जाने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें नोटिस देकर उनसे शपथ-पत्र मांगा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा धर्म के आधार पर मतदाता सूची में आरोप लगाये जाने पर भारत निर्वाचन आयोग मौन क्यों है? भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस देकर शपथ-पत्र मांग कर अपनी खत्म होती विश्वसनीयता को बचाने का काम करे। भा0ज0पा0 सरकार व संगठन के दबाव में मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 110-करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 308 प्रा0पा0 ककरिया को स्थान परिवर्तित करके प्रा0पा0 चौहानपुर पर स्थानान्तरित किये जाने के अनियमित एवं अन्याय पूर्ण निर्णय पर पुनर्विचार करके उक्त मतदान केन्द्र को पूर्वत प्रा0पा0 ककरिया पर बनाये रखे जाने हेतु अथवा ग्राम ककरिया के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र को यथावत रखते हुए ग्राम चौहानपुर के मतदाताओं के लिए एक नया मतदान केन्द्र प्रा0पा0 चौहानपुर पर बनाया जाये।

यूपी में बिजली शिकायतों के निस्तारण में तेजी

लखनऊ, । योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अक्टूबर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में तेजी दिखाई। प्रदेश के पांचों विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम) में इस दौरान कुल 7.41 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7,09,038 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस तरह कुल शिकायतों में से 95.63 प्रतिशत का समाधान किया गया है।डिस्कॉमवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे अधिक करीब 2.54 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में करीब 1.33 लाख, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 1.41 लाख और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में करीब 1.12 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) में 66 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण हुआ।अक्टूबर में पांचों डिस्कॉम में सबसे अधिक शिकायतें बिजली आपूर्ति से संबंधित प्राप्त हुईं। इसके अलावा उपभोक्ताओं ने बिजली सेवाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी दर्ज कराया। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 को महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है। शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निस्तारण के साथ ही प्रत्येक शिकायत का समाधान उपभोक्ता की संतुष्टि के आधार पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

ठाकुरगंज-दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर गिरफ्तार

लखनऊ। राजधानी के थाना ठाकुरगंज पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था और उसकी हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया गया।हरदोई निवासी पिता ने तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी उमा की शादी वर्ष 2022 में मुकेश के साथ की थी। शादी के बाद से ही दामाद दहेज के लिए बेटी को मारता-पीटता था। 10 नवंबर की सुबह दामाद ने फोन कर बताया कि उमा मर गई है। मायके वाले पहुंचे तो बेटी जमीन पर मृत पड़ी थी।पुलिस ने पति मुकेश रावत (23) और ससुर कामता प्रसाद (50) को माधोपुर सकरी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

दिव्यांगजनों को स्थायी रोजगार से ही बनाया जा सकता है समृद्ध एवं सशक्तः कश्यप

लखनऊ, । पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, कुलसचिव डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ तथा जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिये। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के पिछड़ा वर्ग के पात्र उम्मीदवारों तक पहुंचाना सरकार की मंशा है, जिसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता एवं उदासीनता बर्दाशत नहीं की जायेगी। योगी सरकार द्वारा समाज के दिव्यांगजन हेतु विभिन्न योजनाऐं चलायी जा रही हैं ताकि दिव्यांगजन को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। दिव्यांगजनों को स्थायी रोजगार के माध्यम से ही समृद्ध एवं सशक्त बनाया जा सकता है, जिसके लिए निगम एवं निकाए के साथ सामंजस्य स्थापित कर इस दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य किया जाए ताकि दिव्यांगजन को स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। दिव्यांगता पेंशन भुगतान में होने वाले विलंब को लेकर मंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए पात्रों को शीघ्र दिव्यांगता पेंशन उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिये। 3 दिसम्बर को 'अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' के अवसर पर भव्य आयोजन कराने और मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव अभी से तैयार कर कार्यवायी के निर्देश दिये। बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अतिम सिंह व रणजीत सिंह एवं उप निदेशक अमित राय के अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक विकास शर्मा के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थें।

मदेयगंज-त्रिवेणीनगर में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गुरुवार को नवनिर्मित पुलिस चौकी त्रिवेणीनगर का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पुलिस उपायुक्त मध्य अर्पित विजयवर्गीय ने फीता काटकर किया।इस अवसर पर अपर पुलिस उपायुक्त जितेन्द्र कुमार दुबे और सहायक पुलिस आयुक्त अंकित कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि नई चौकी के खुलने से क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ेगी, अपराधों पर अंकुश लगेगा और लोगों को त्वरित सहायता मिलेगी।स्थानीय लोगों ने चौकी खुलने पर खुशी जताते हुए कहा कि अब उन्हें शिकायतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि हर फरियादी की बात संवेदनशीलता से सुनी जाए।

दीदी मिठाई छीन लेती है, हमें मारती है

केयरटेकर अंकिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लखनऊ, । बागपत में दीपावली के मौके पर एक बाल संरक्षण गृह बालगृह की खौफनाक हकीकत उस वक्त सामने आई, जब खुद जिलाधिकारी दिव्यांशु पटेल की पत्नी स्वाति सहगल वहां पहुंचीं। बच्चों को मिठाई बांटने गईं स्वाति के सामने बच्चों ने मारपीट, धमकी और उत्पीड़न का जो दर्द बयां किया, उसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। डीएम के सख्त निर्देश के बाद बालगृह की केयरटेकर के खिलाफमुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दीदी हमें मिठाई नहीं खाने देतीं दीपावली के दिन स्वाति सहगल अपनी बेटी और सास के साथ सरूरपुर कलां गांव स्थित शिक्षतिज बाल एवं शिशु गृह पहुंची थीं। उन्होंने बच्चों को गोद में दुलारा और उन्हें मिठाई व उपहार बांटे। वह बच्चों से बात कर रही थीं, तब एक मासूम का दर्द छलक उठा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, दीदी हमें मिठाई नहीं खाने देतीं, ये खुद खा लेती हैं। यह सुनकर स्वाति सहगल हैरान रह गईं। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग बच्चों से एकांत में बात की। बच्चों ने बताया कि उनके साथ मारपीट की जाती है और सामान मांगने पर उन्हें धमकाया जाता है। एक बच्चे ने यहां तक कहा कि आपके जाने के बाद ये सारे गिफ्ट और मिठाइयां छीनकर अपने घर ले जाएंगी। बालगृह से लौटने के बाद स्वाति सहगल ने पूरी घटना डीएम दिव्यांशु पटेल को बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने तुरंत जिला प्रोबेशन अधिकारी राहुल वर्मा को जांच के सख्त निर्देश दिए। 10 नवंबर को प्रोबेशन अधिकारी ने बालगृह का औचक निरीक्षण किया और बच्चों के बयान दर्ज किए। जांच में बच्चों की शिकायतों की पुष्टि होने के बाद, चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वंदना गुप्ता की तहरीर पर बागपत कोतवाली पुलिस ने केयरटेकर अंकिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जेलों में सुरक्षा और सुधार पर डीजी जेल ने की बड़ी समीक्षा

रात की गश्त से लेकर सीसीटीवी तक दिए सख्त निर्देश

लखनऊ।कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश के महानिदेशक कारागार पी. सी. मीना ने कारागार मुख्यालय लखनऊ से प्रदेश के सभी जेल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की।बैठक में सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक, अधीक्षक और प्रभारी अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में नए जेल वार्डरों की नियुक्ति जल्द व नव चयनित जेल वार्डरों की नियुक्ति की सभी औपचारिकताएं तय समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए। डीजी ने कहा कि नियुक्ति में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।वही कहा कि मानव संपदा पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट होगा।सभी कार्मिकों के सेवा अभिलेख और वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को अभिलेख समयबद्ध ढंग से पूर्ण और अपडेट करने के निर्देश दिए गए।इसके अलावा ई-प्रिजन्स अर्ली रिलीज प्रोसेसिंग मॉड्यूल को शुरू करने की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया, ताकि पात्र कैदियों की समय से रिहाई हो सके। डीजी जेल नें कारागारों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मुख्यालय स्थित वीडियो वॉल से कनेक्टिविटी की समीक्षा की गई। डीजी ने कैमरों की निर्बाध कनेक्टिविटी और प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए अधिकारियों द्वारा की जा रही रात्रिकालीन गश्त की समीक्षा की गई। डीजी ने नियमित रूप से रात्रि गश्त सुनिश्चित करने और सुरक्षा के प्रति पूरी सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। महानिदेशक कारागार ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूरी की जाए।

खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं को लेकर उद्यमियों को किया जाए जागरूक-केशव

लखनऊ, । उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव



बीएल मीणा को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण 2023 संबंधी योजनाओं और उनमें उपलब्ध वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। किसानों, कृषि उद्यमियों, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों , किसान उत्पादक संगठनों तथा महिला उद्यमियों को इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, भंडारण और निर्यात के क्षेत्र में आगे आ सकें। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है। इसके लिए विभाग योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करे। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्लांट, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर 35 प्रतिशत, अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है। इकाइयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर भी 25 से 35 प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती है। भूमि खरीद पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट तथा पात्र परियोजनाओं में बाह्य विकास शुल्क पर 75 प्रतिशत छूट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन, एग्रो प्रोसेसिंग

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर 5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी

क्लस्टर और बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने के लिए भी आकर्षक अनुदान की व्यवस्था है। पात्र परियोजनाओं में 10 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। स्वयं सहायता समूहों, एफ्पीओ और किसानों को विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण एवं भंडारण के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है।महिला उद्यमियों को पात्र सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 90 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा निर्धारित देशों को छोड़कर निर्यात पर 25 प्रतिशत फ्रेट सब्सिडी का प्रावधान है।

गोपालकों को अपशब्ध कहकर मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण का अपमान किया

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि ''गोपालकों ''को अपशब्द कहकर



प्रकारांतर में गोपाल अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण का जो अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से किया है वो अक्षम्य है। पहले अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के 'चढ़ावा-चंदा-दान' चोरी में एक बड़े गिरोह के साथ संलिप्त रहे और राज न खुल जाए इस डर से उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब भगवान कृष्ण पर वार कर रहे हैं। ये सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता को स्थापित करने के मंसूबे के कारण ऐसे कुवचन बोल रहे हैं। इसी दुर्भावना के कारण मुख्यमंत्री ने वाराणसी में पाल समाज को लाठी से पिटवाया था और गडरियों के होल्कर समाज से आने वाली शिवजी की परम भक्त राजमाता देवी अहिल्याबाई की शिवलिंग ली हुई प्रतिमा का वाराणसी में घोर तिरस्कार किया था। ये न भगवान शिव के सगे हैं, न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के और न ही देवी अहिल्याबाई जी के। ये इतने कमजोर पड़ गये हैं कि अब उत्तर प्रदेश में किसी और 'दुश्मुखी' को बुलाया जा रहा है। इन दोनों में कई बातें समान हैं, वेशभूषा का स्वांग, दुर्वचनी जुबान और भगवान राम और भगवान कृष्ण का सरेआम अपमान करना। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता कह रही है कि अब इनका प्रभाव शून्य हो गया है। अगर इनका प्रभाव शेष होता तो वो ऐसे असामाजिक व्यक्ति को कभी भी अपने प्रदेश में आने की अनुमति नहीं देते, जो उनके ही दिये गये नारे को सरेआम ठुकराकर समाज को बाँट रहा है। व्यक्ति जब कमजोर हो जाता है तो अनैतिक सहारा ढूंढने लगता है। अगर इनमें अंशमात्र भी शक्ति, सामर्थ्य और साहस शेष होगा तो वो ऐसे ईश विरोधी वक्तव्य देनेवालों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देंगे लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इन्हीं के विचारवंशी हैं और वचनवंशी भी। दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं। पुन: दोहरा रहे हैं क्योंकि एक बार में वो पढ़ नहीं पाते हैं और दस बार में भी समझ नहीं पाते हैं। कृपया सनातनी वस्त्रों को पहनकर इतनी निम्नस्तरीय भाषा न बोलें। अपने व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को बाहर लाने से पहले सोचें कि आप अभी कुछ

सपा मुखिया ने योगी के बयान पर किया पलटवार

दिनों के लिए ही सही, एक सम्प्रदाय के सम्माननीय पद के साथ-साथ एक संवैधानिक पद पर भी विराजमान हैं। अपना श्रीमुख खोलने से पहले, सार्वजनिक मर्यादा के साथ ही, उन पदों की प्रतिष्ठा का भी ध्यान-मान रखें। उन्होंने कहा कि बात इतनी सी है कि ये 2024, 2026 की हार से डर गये हैं इसीलिए इनके बोल बिगड़ गये हैं। ये 2027 में हमेशा के लिए हारेंगे। अगर ये जीत रहे होते तो हमारी नहीं, अपनी और अपनी उपलब्धि की बात करते। ये जितना बुरा बोलेंगे, उतनी ही बुरी हार हारेंगे क्योंकि 2027 का चुनाव अब पांच प्रतिशत अहंकारियों, वर्चस्ववादियों, प्रभुत्ववादियों बनाम 95 प्रतिशत पीडीए के बीच हो गया है। अब तो पीडीए में हर समाज के पीड़ित, दुखी, अपमानित शामिल हो गये हैं, इसीलिए पीडीए का जनाधार 85 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है।

बीजेपी ने बनाये 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारी

लखनऊ, । उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 403 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विधानसभा प्रभारियों के नामों का ऐलान किया। ये अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से समन्वय कर पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएंगे। गोरखपुर सदर सीट से विवेकानंद वर्मा, अमरोहा सीट से सुरेश सैनी, गाजियाबाद सीट से मीनाक्षी, मोदीनगर सीट से गोविंद चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने श्एक्सश् पर पोस्ट कर बीजेपी, गोरखपुर क्षेत्र के नवनियुक्त विधानसभा प्रभारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।बीजेपी ने संगठनात्मक प्रांतों के हिसाब से विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनमें अवध क्षेत्र में 82, काशी क्षेत्र में 71, कानपुर-बुंदेलखंड में 52, पश्चिमी यूपी में 71, गोरखपुर क्षेत्र में 62 और ब्रज क्षेत्र में 65 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।सुरेश सैनी अमरोहा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी बने है। मुरादाबाद की बिलारी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।सुरेश सैनी 2012 में मुरादाबाद देहात और 2016 के उपचुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बिलारी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वे तीनों चुनाव सपा प्रत्याशी से हार गए थे।मीनाक्षी भराला को गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी बनाई गई हैं।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों की 9-9 टीमें रहेंगी सक्रिय

लखनऊ,(आज समाचार सेवा)। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश में व्यय



संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में गुरुवार को योजना भवन, लखनऊ में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्वाचन के दृष्टिगत अभी से सक्रिय एवं सतर्क रहते हुए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को धनबल एवं प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए नगदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए। बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी धनराशि जमा होने एवं निकासी तथा अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां निर्वाचन व्यय की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य जीएसटी, केन्द्रीय जीएसटी, कस्टम, राज्य नागरिक उड्डयन ,रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, सशस्त्र सीमा बल, पुलिस, आबकारी, फॉरेस्ट, परिवहन, रेलवे, राजस्व अभिसूचना निदेशालय, सहकारिता सहित सभी संबंधित विभाग अपने.अपने कार्यक्षेत्र में सतर्कता एवं सक्रियता के साथ कार्य करें। व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा सामान्य निर्वाचन एवं वर्ष 2024 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान हुई जब्ती तथा पिछले छह माह की गैर-निर्वाचन अवधि की गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों का

संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन की प्रक्रिया तेज

विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का वर्गीकरण कर आवश्यक निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में निर्वाचन के दौरान जब्ती की कार्यवाही को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित वेब पोर्टल के संचालन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत राज्य नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों तथा उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों की ऑनबोर्डिंग और लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी ही नामित किए जाएं तथा बैठकों में संबंधित नोडल अधिकारी की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी अन्य कनिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में भेजने की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रलोभनकारी वस्तुओं एवं मुफ्त वितरण से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण निर्धारित दिशा.निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए। परिवहन, जीएसटी, कस्टम एवं रेलवे विभागों के अधिकारियों के साथ ट्रांजिट के दौरान जांचए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी तथा विभिन्न एजेंसियों के कार्यक्षेत्र से जुड़े व्यावहारिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में ईडी के उपनिदेशक पीयूष, संयुक्त आयुक्त आयकर भारत सरकार अमित कुमार सिंह चौहान, नॉरकोटिक्स क्षेत्रीय निदेशक श्रीपत पाण्डेय, राजस्व अभिसूचना निदेशालय के अपर निदेशक संदीप कुमार सिंह, सीजीएसटी अपर आयुक्त पीयूष कटियार राज्य नागरिक उड्डयन संयुक्त निदेशक मनोज तिवारी आदि सहित विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।